भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1136
13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार

1136. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई), देश के बड़े रोजगार देने वाले उद्योगों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सृजित रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी एजेंसियों द्वारा निवेश की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रों के रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर डेटा जारी करता है। वर्ष 2019-20 के उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों में से 12.22 % का योगदान दिया है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पांच वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	रोजगार (लाखों में)
2015 - 16	17 . 65
2016 - 17	18 . 53
2017 - 18	19 . 33
2018 - 19	20 . 05
2019 - 20	20 . 32

स्रोत: 2015-16, 2016-1, 2017-18, 2018-19 और 2019–20 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संपदा योजना प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता बढ़ाने, ऑफ-फार्म रोजगार सृजित करने, घरेलू निवेश का लाभ उठाने और अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। वैश्विक खाद्य चैंपियन तैयार करने और रोजगार उत्पन्न करने हेतु प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के माध्यम से उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है। वर्ष 2020-21 से प्रधान मंत्री-सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना (पीएम-एफएमई) का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 2 लाख सूक्ष्म अनौपचारिक इकाइयों का उन्नयन/औपचारिकीकरण करना है । सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को भी अनुमति दे दी है।

अप्रैल, 2014 से मार्च, 2022 तक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त कुल एफडीआई 5.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। साथ ही दिनांक 30.11.2022 तक पीएमकेएसवाई के विभिन्न योजना घटकों के अंतर्गत 679 पूर्ण परियोजनाओं ने भी 9511.9 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाया है।

*****